RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 16 से 22 अगस्त 2025 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 12 | अंक-54 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

मध्यप्रदेश में बीईएमएल की नई यूनिट का शिलान्यास: 1800 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट से युवाओं की बदलेगी तकदीर

रायसेन: मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में एक ऐतिहासिक कदम उठा, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) की रेल हब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 'ब्रह्मा' का शिलान्यास किया। 1800 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना से न केवल प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर बदलेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में वेद मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

यह यूनिट 148 एकड़ में फैली होगी और हाईवे, रेल व हवाई मार्ग से जुड़ी होगी। यहाँ वंदे भारत और अमृत भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के लाइटवेट एल्यूमीनियम कोच बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह परियोजना मध्यप्रदेश को आधुनिक और औद्योगिक रूप से समृद्ध प्रदेश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश की प्रगति और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की सराहना की। सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे 'रोजगार की गंगोत्री' करार देते हुए कहा कि यह यूनिट 5000 से अधिक लोगों को रोजगार देगी और स्थानीय एमएसएमई इकाइयों को भी लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने स्वदेशी अभियान के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बीईएमएल के प्रेसिडेंट-सीएमडी शांतनु राय ने बताया कि यह यूनिट 18 महीनों में पहला रेल कोच तैयार कर लेगी और भविष्य में रक्षा उत्पादों का निर्माण भी करेगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो संदेश में कहा कि यह परियोजना 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के संकल्प को साकार करेगी। यह यूनिट मध्यप्रदेश को रेलवे मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का केंद्र बनाएगी। यह परियोजना न केवल आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक बदलाव का भी आधार बनेगी।

सुजलॉन की पहली तिमाही: मुनाफा 7% बढ़ा, रेवेन्यू में 55% की उछाल

भोपाल: सुजलॉन एनर्जी ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (Q1 FY26) में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 7% बढ़कर ₹324 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹302 करोड़ था। इसके साथ ही, कंपनी का रेवेन्यू 55% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ ₹3,131 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल ₹2,015 करोड़ था। यह वृद्धि कंपनी की रिकॉर्ड 444 मेगावाट की पहली तिमाही डिलीवरी और मजबूत ऑर्डर बुक के कारण संभव हुई।

सुजलॉन का EBITDA 62% बढ़कर ₹599 करोड़ रहा, जबकि EBITDA मार्जिन 18.4% से सुधरकर 19.22% हो गया। कंपनी की 5.7 गीगावाट की ऑर्डर बुक और ₹1,620 करोड़ की नेट कैश स्थिति इसके मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाती है। हालांकि, तिमाही-दर-तिमाही आधार पर रेवेन्यू में 17% और मुनाफे में 73% की कमी देखी गई, जो पिछले तिमाही में मिले टैक्स क्रेडिट और इस तिमाही में बढ़े टैक्स खर्च के कारण थी।

कंपनी के शेयरों ने पिछले छह महीनों में निवेशकों को 21% का रिटर्न दिया है, जो इसकी मजबूत बाजार स्थिति और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती मांग को दर्शाता है। सुजलॉन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं में बेहतर निष्पादन और रणनीतिक पहल ने इसे निवेशकों के बीच आकर्षक बनाया है।

विश्लेषकों का मानना है कि सुजलॉन की मजबूत ऑर्डर बुक और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग कंपनी के लिए भविष्य में और अवसर लाएगी। हालांकि, तिमाही-दर-तिमाही अस्थिरता और मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) के इस्तीफे जैसे कारक निवेशकों के लिए निगरानी के बिंदु हो सकते हैं।

कुल मिलाकर, सुजलॉन का यह प्रदर्शन नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में इसकी स्थिति को मजबूत करता है। निवेशक और हितधारक अब कंपनी की अगली तिमाही के नतीजों पर नजर रखेंगे, जो इसकी दीर्घकालिक रणनीति को और स्पष्ट करेंगे।

स्रोत: NSE

बीमा क्षेत्र में 100% FDI से रोजगार के नए अवसर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

भोपाल: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में घोषणा की कि भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने से बाजार में नए खिलाड़ी आएंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह घोषणा 1 फरवरी, 2025 के केंद्रीय बजट में की गई थी। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि उन्नत तकनीकों और स्वचालन के माध्यम से बीमा क्षेत्र में तेजी से अंडर राइटिंग और दावा प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा, जिससे लागत कम होगी और समग्र दक्षता में सुधार होगा।

बीमा अधिनियम, 1938 के तहत निवेश को विनियमित किया जाता है, जो सुरक्षा, तरलता और पॉलिसी धारकों के हितों को प्राथमिकता देता है। अधिनियम में निवेश के समय, तरीके, शर्तों और स्वीकृत प्रतिभूतियों जैसे सरकारी बॉन्ड में एक निश्चित प्रतिशत निवेश अनिवार्य है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा 150% की सॉल्वेंसी सीमा सुनिश्चित की जाती है, और बीमा कंपनियों को अपने फंड भारत के बाहर निवेश करने की अनुमति नहीं है। यह पॉलिसी धारकों की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करता है।

सीतारमण ने बताया कि IRDAI की निगरानी से पारदर्शिता, उचित व्यावसायिक प्रथाएं और शिकायत निवारण में दक्षता सुनिश्चित होती है। यदि कोई बीमा कंपनी पॉलिसी धारकों के हितों के खिलाफ कार्य करती है, तो IRDAI को कंपनी के बोर्ड को हटाकर एक प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय बीमा कंपनियों (विदेशी निवेश) नियम, 2015, लाभांश भुगतान और बोर्ड संरचना जैसे परिचालन पहलुओं को नियंत्रित करते हैं।

X पर इस कदम को लेकर उत्साह देखा गया, जहां उपयोगकर्ताओं ने इसे आर्थिक विकास और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने वाला बताया। विश्लेषकों का मानना है कि यह नीति वैश्विक बीमाकर्ताओं को आकर्षित करेगी और क्षेत्र में 7.1% की वृद्धि को बढ़ावा देगी। यह कदम भारत के बीमा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक लाभ की उम्मीद है।

स्रोत : Sansadtv.nic.in & X.com

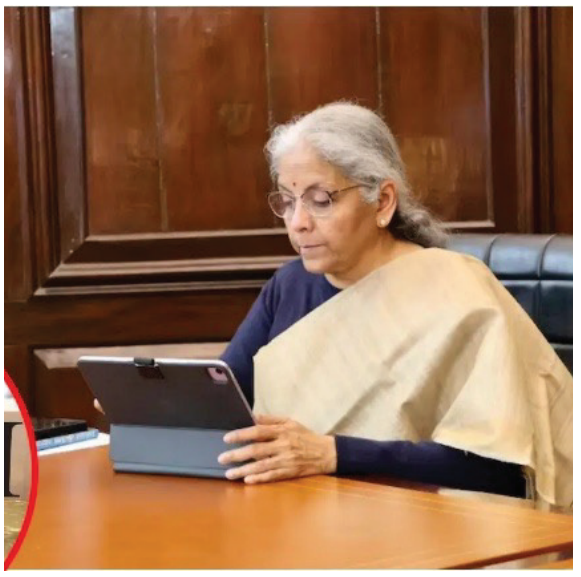

NSDL की लिस्टिंग के बाद पहली तिमाही: मुनाफा 15% बढ़ा, रेवेन्यू में 7% की गिरावट

भोपाल: हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) ने अपनी पहली तिमाही (Q1 FY26) के नतीजे जारी किए हैं, जो निवेशकों के लिए मिश्रित संदेश लेकर आए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा साल-दर-साल (YoY) 15.2Rio% बढ़कर ₹89.62 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 14.8% की वृद्धि दर्शाता है। यह मजबूत लाभ वृद्धि परिचालन दक्षता और अन्य आय में सुधार के कारण हुई, जैसा कि हाल के विश्लेषणों में बताया गया है।

हालांकि, कंपनी का रेवेन्यू 7% घटकर ₹312 करोड़ रहा, जो पिछले साल की पहली तिमाही में ₹337 करोड़ था। यह गिरावट तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) 14% की कमी को भी दर्शाती है। इसके बावजूद, NSDL ने अपने EBITDA में 18% की वृद्धि दर्ज की, जो ₹95.18 करोड़ तक पहुंच गया, और EBITDA मार्जिन 30.5% तक सुधर गया, जो पिछले साल 23.8% था।

NSDL के शेयरों ने अपनी लिस्टिंग के बाद से शानदार प्रदर्शन किया है, जो इसके इश्यू प्राइस से 60% से अधिक चढ़ चुके हैं। यह निवेशकों के भरोसे और कंपनी के मजबूत बिजनेस मॉडल को दर्शाता है। कंपनी की परिचालन रणनीतियों और बाजार की स्थिति ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विश्लेषकों का कहना है कि रेवेन्यू में कमी के बावजूद, NSDL का मुनाफा और मार्जिन में सुधार कंपनी की दीर्घकालिक विकास क्षमता को दर्शाता है। बाजार के जानकारों का मानना है कि डिजिटल और वित्तीय सेवाओं की बढ़ती मांग NSDL के लिए भविष्य में और अवसर पैदा कर सकती है।

कुल मिलाकर, NSDL की पहली तिमाही के नतीजे कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और बाजार में इसके बढ़ते प्रभाव को उजागर करते हैं। निवेशकों और हितधारकों की नजर अब अगली तिमाही के प्रदर्शन पर होगी, जो कंपनी की रणनीतिक दिशा को और स्पष्ट करेगी।

स्रोत : NSE

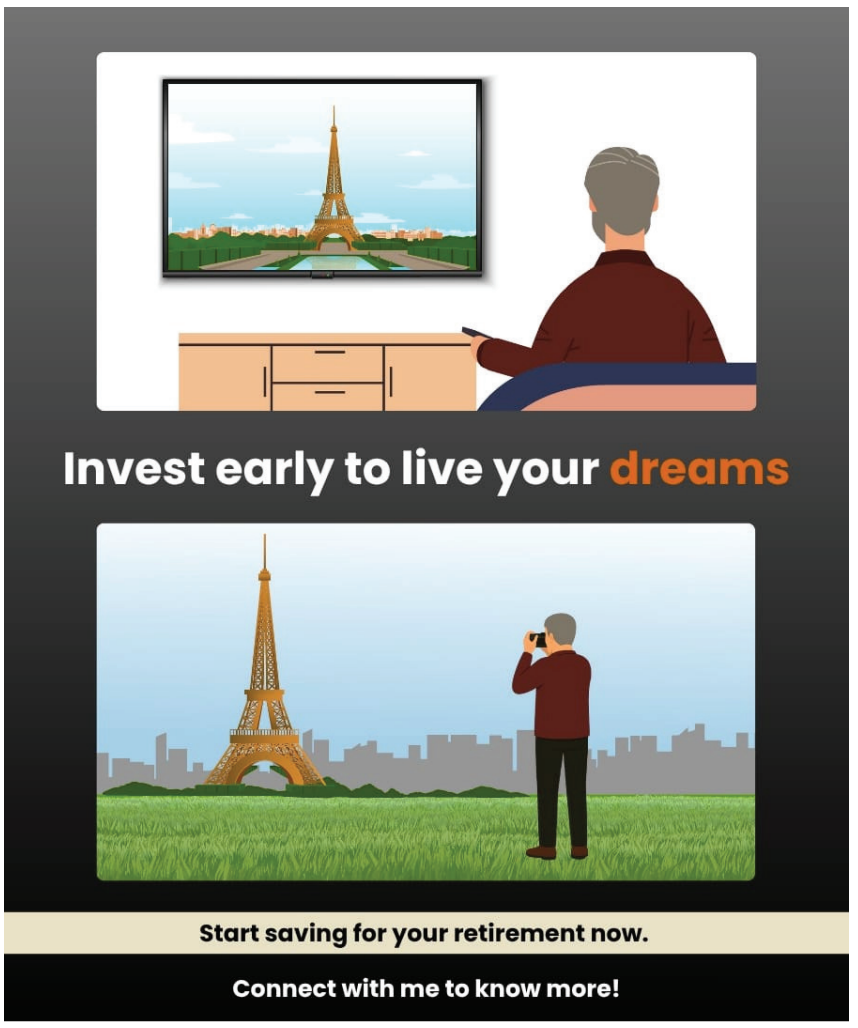

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

The Journey of India's Economy (1947–2025): From Independence to Innovation

The Indian economy's journey from 1947 to 2025 is a story of resilience, reform, and reinvention. Over nearly eight decades, India has transformed from a largely agrarian society to one of the world's fastest-growing economies, powered by industry, services, and innovation. Each era brought unique challenges and opportunities, shaped by the vision of successive governments and evolving policies.

1947–1965: Foundations of a Mixed Economy

When India gained independence in 1947, it inherited an underdeveloped economy, low per capita income, poor infrastructure, and heavy dependence on agriculture. The first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, adopted a mixed economy model, blending state-led planning with private enterprise. The First Five-Year Plan (1951–56) prioritized agriculture, irrigation, and community development, while the Second Five-Year Plan (1956–61) emphasized heavy industries through the Public Sector Undertakings (PSUs). Institutions like the Planning Commission and the Reserve Bank's developmental role became pivotal.

1965–1980: Green Revolution and Self-Reliance

Food shortages and wars in 1962 and 1965 exposed vulnerabilities. Under Lal Bahadur Shastri and later Indira Gandhi, India initiated the Green Revolution boosting wheat and rice production through improved seeds, fertilizers, and irrigation. Nationalization of banks in 1969 expanded rural credit access, while import-substitution industrialization aimed to reduce foreign dependence.

1980–1991: Gradual Liberalization

During the 1980s, under Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, the economy saw gradual liberalization, reducing licensing restrictions, promoting technology imports, and encouraging small-scale entrepreneurship. Infrastructure development, especially in telecom and transport, laid the groundwork for future reforms. By 1991, high fiscal deficits and a balance of payments crisis forced India to seek IMF assistance.

1991–2004: Economic Liberalization and Global Integration

In 1991, under Prime Minister P.V. Narasimha Rao and Finance Minister Dr. Manmohan Singh, India embraced sweeping reforms, dismantling the License Raj, reducing tariffs, encouraging foreign direct investment (FDI), and reforming capital markets. The service sector, especially IT and software exports, surged. The economy averaged over 6% growth, positioning India as an emerging global player. Successive governments, including the Vajpayee administration, emphasized infrastructure through the Golden Quadrilateral Project and telecom expansion.

2004–2014: Inclusive Growth and Social Welfare

Under the UPA governments led by Dr. Manmohan Singh, India experienced strong GDP growth, peaking at over 9% in 2007–08 before the global financial crisis. Policies like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), Right to Education, and expansion of rural infrastructure aimed to make growth more inclusive. The economy remained resilient, though challenges like inflation and fiscal deficits persisted.

2014–2025: Structural Reforms and Digital Transformation

Since 2014, under Prime Minister Narendra Modi, India has focused on structural reforms, infrastructure expansion, and digital governance. Landmark initiatives included:

- Goods and Services Tax (GST) simplifying indirect taxation.
- Make in India and Production-Linked Incentive (PLI) schemes to boost manufacturing.
- Digital India driving financial inclusion through platforms like UPI.
- Large-scale infrastructure projects including expressways, metro systems, and renewable energy expansion.

By 2025, India is the world's 4th-largest economy, a hub for startups, renewable energy innovation, and a leader in digital payments.

Conclusion

The Indian economy's evolution from 1947 to 2025 reflects adaptability and reform. From agrarian beginnings to becoming a global technology and services powerhouse, each phase driven by visionary policies, political will, and public resilience has contributed to India's transformation. Looking ahead, sustained reforms, green growth, and skill development will be key to realizing the vision of a developed India by 2047.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

IRCTC का मुनाफा पहली तिमाही में 7% बढ़ा, ₹331 करोड़ तक पहुंचा

भोपाल: भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 7% बढ़कर ₹331 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹308 करोड़ था। इसके साथ ही, IRCTC का राजस्व भी 4% की वृद्धि के साथ ₹1160 करोड़ तक पहुंचा, जो पिछले साल ₹1116 करोड़ था। यह जानकारी कंपनी की हालिया वित्तीय रिपोर्ट में सामने आई है।

IRCTC की इस वृद्धि का मुख्य कारण ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बढ़ोतरी और पर्यटन सेवाओं की मांग में इजाफा है। कंपनी रोजाना औसतन 12 लाख टिकट बुक करती है, जो भारतीय रेलवे की डिजिटल पहुंच और इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। इसके अलावा, IRCTC की खानपान सेवाएं और पर्यटन पैकेज, जैसे भारत गौरव ट्रेन और तीर्थ यात्रा पैकेज, भी राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की मजबूती और उपयोगकर्ता-अनुकूल सेवाओं ने IRCTC को इस प्रतिस्पर्धी बाजार में आगे रखा है। कंपनी ने हाल ही में अपनी मोबाइल ऐप और वेबसाइट में सुधार किए हैं, जिससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया और तेज व सुगम हुई है। इसके अलावा, IRCTC ने नई ट्रेनों और पर्यटन स्थलों को अपने पैकेज में शामिल किया है, जिसने यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया है। IRCTC के प्रबंध निदेशक ने कहा, "हमारा ध्यान ग्राहक संतुष्टि और डिजिटल नवाचार पर है। हम भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं।" यह वृद्धि भारतीय रेलवे के डिजिटल और पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक योगदान को दर्शाती है।

स्रोत : बिज़नेस स्टैण्डर्ड

PSU Banks Write Off ₹5.82 Lakh Crore in 5 Years: MoS Finance

Public sector banks (PSBs) in India have written off bad loans totalling approximately ₹5.82 lakh crore over the past five financial years, as disclosed by Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary in a written reply to the Rajya Sabha. In the fiscal year 2024-25 alone, PSBs wrote off ₹91,260 crore, a decrease from ₹1.15 lakh crore in the previous fiscal. The highest write-off was recorded in 2020-21 at ₹1.33 lakh crore, followed by ₹1.27 lakh crore in 2022-23 and ₹1.16 lakh crore in 2021-22. Despite these write-offs, banks recovered around ₹1.65 lakh crore, representing about 28% of the total written-off amount during this period.

These write-offs, governed by Reserve Bank of India (RBI) guidelines, involve non-performing assets (NPAs) fully provisioned for over four years, as per bank board policies. Importantly, write-offs do not waive borrower liabilities; banks continue to pursue recovery through legal iavenues such as civil courts, Debt Recovery Tribunals, and the Insolvency and Bankruptcy Code. Chaudhary emphasized that these actions do not benefit borrowers, who remain liable for repayment.

Analysts suggest that while write-offs help clean up bank balance sheets, the recovery rate highlights challenges in resolving NPAs effectively. The government's push for stronger recovery mechanisms and reforms in PSBs aims to address these issues. Additionally, Chaudhary noted that over ₹21.68 lakh crore has been disbursed under the Pradhan Mantri Mudra Yojana over the same period, indicating continued lending activity.

As PSBs navigate this complex landscape, the focus remains on improving asset

quality and recovery processes to minimize future write-offs. Stakeholders will closely monitor how these efforts impact the banking sector's financial health in the coming years.

Source: Sansadtv.nic.in

Berger Paints Targets ₹20,000 Crore Revenue by 2030

Bhopal: Berger Paints India Limited, the nation's second-largest paint manufacturer, has set an ambitious goal of achieving a ₹20,000 crore turnover by 2030, as announced by MD and CEO Abhijit Roy during the company's 101st Annual General Meeting on August 12, 2025. Despite economic challenges, Berger achieved over 7% volume growth last year, holding a 20% market share in the organized paint segment. Roy emphasized the company's resilience, focusing on growth in decorative paints, construction chemicals, and industrial segments.

Berger is prioritizing innovation, digitalization, and urban market expansion to meet this target. The company ranks third in the fast-growing construction chemicals and waterproofing sector and leads in protective coatings, bolstered by India's infrastructure boom and 'Make in India' initiatives. Despite rising raw material costs, Berger plans to maintain stable product prices, balancing costs with softer input prices. With a current revenue of ₹11,199 crore (FY24), Berger aims to nearly double its turnover through strategic capacity expansion and a robust distribution network, positioning itself for strong growth by 2030.

Source: Business Standard

समवर्धन मदरसन पर अमेरिकी टैरिफ का कोई बड़ा प्रभाव नहीं

भोपाल:ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माता समवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ का कंपनी के परिचालन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी के सह-अध्यक्ष ने कहा कि समवर्धन मदरसन की अधिकांश बिक्री यूएसएमसीए (यूएस-मेक्सिको-कनाडा समझौता) के अनुरूप है, जिसके कारण टैरिफ का असर न्यूनतम रहेगा। इसके अलावा, गैर-यूएसएमसीए अनुपालित हिस्सों के लिए, कंपनी ग्राहकों के साथ टैरिफ लागत को साझा करने के लिए समझौते कर रही है।

समवर्धन मदरसन, जो ऑटोमोटिव वायरिंग हार्नेस, प्लास्टिक कंपोनेंट्स और अन्य हिस्सों की आपूर्ति करती है, ने अपनी मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक योजना के कारण इस स्थिति को संभालने की क्षमता दिखाई है। कंपनी का कहना है कि वह बदलते टैरिफ परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए अच्छी तरह तैयार है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ रही है, और कई भारतीय कंपनियां अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव का आकलन कर रही हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि समवर्धन मदरसन की विविध बाजार उपस्थिति और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण ने इसे इस चुनौती से निपटने में मदद की है। कंपनी ने हाल के वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूंजी निवेश (कैपेक्स) की योजना बनाई है, जो इसके विकास को और गति देगी।

कंपनी के शेयरों में इस खबर के बाद तेजी देखी गई, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। समवर्धन मदरसन ने कहा कि वह अपने ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंधों और तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके।

स्रोत : इकनोमिक टाइम्स

Zepto Secures Rs 400 Crore from Motilal Oswal to Fuel IPO Plans

Bhopal: Motilal Oswal Financial Services Limited (MOFSL) has invested Rs 400 crore in quick-commerce giant Zepto, acquiring 7.55 crore compulsorily convertible preference shares (CCPS) in an all-cash deal. This investment, part of MOFSL's treasury portfolio for long-term returns, values Zepto at approximately $5.4 billion (Rs 47,298 crore), signaling strong investor confidence in the startup's growth trajectory. The transaction, disclosed in a stock exchange filing, follows MOFSL's earlier $350 million round in Zepto in November 2024.

Founded in 2021 by Aadit Palicha and Kaivalya Vohra, Zepto has revolutionized grocery delivery with its 10-minute model, operating across multiple Indian cities. The company's revenue surged to Rs 11,109 crore in FY25 from Rs 4,454 crorein FY24, reflecting its rapid expansion. This investment is part of Zepto's strategy to boost domestic shareholding ahead of its planned 2026 IPO, aiming to increase Indian ownership to over 50%. Recent investments from Elcid Investments (Rs 7.5 crore) and MapmyIndia (Rs 25 crore) further support this goal.

The deal is part of a Rs 1,000 crore funding round, with Rs 600 crore expected from other domestic investors via secondary share purchases. Zepto is also finalizing a primary round led by General Catalystand Avenir Growth, with its founders raising Rs 1,500 crore through debt financing. As competition intensifies with rivals like Blinkit and Swiggy Instamart, Zepto is focusing on improving unit economics and reducing cash burn to strengthen its financials for the public listing. This investment underscores the growing potential of India's quick-commerce sector.

Source: The Economic Times

Cohance Lifesciences ने अमेरिकी इकाई में 10 मिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की

Bhopal: Cohance Lifesciences ने अपनी अमेरिकी सहायक कंपनी, एनजे बायो, प्रिंसटन, न्यू जर्सी में cGMP बायोकॉन्जुगेशन सुइट के विस्तार के लिए 10 मिलियन डॉलर (लगभग ₹83 करोड़) के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश एंटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट्स (ADC) नवाचार को गति देने के उद्देश्य से किया गया है, जो कैंसर उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यह घोषणा 12 अगस्त 2025 को की गई और इसे वैश्विक फार्मा उद्योग में भारत की बढ़ती उपस्थिति का संकेत माना जा रहा है।

Cohance, जो पहले रेडिको खेतान की फार्मा इकाई थी, ने हाल के वर्षों में तेजी से विस्तार किया है। कंपनी ने हैदराबाद में नई cGMP ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सुविधा के लिए ₹230 मिलियन का निवेश भी नियोजित किया है। FY25 में, कंपनी का राजस्व 9% बढ़कर ₹2,610 करोड़ हो गया, और यह ₹36 करोड़ की नेट कैश पॉजिटिव स्थिति में है।

यह कदम Cohance को प्रारंभिक विकास से लेकर देर-चरण के क्लिनिकल ट्रायल तक नवाचार का समर्थन करने में सक्षम बनाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि यह निवेश भारत के फार्मा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करेगा, जिससे रोजगार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

स्रोत : इकनोमिक टाइम्स

L&T Secures ₹15,000 Crore Deal for Adani Power's 6,400 MW Thermal Project

Bhopal: Larsen & Toubro (L&T) has clinched an ultra-mega contract worth over ₹15,000 crore from Adani Power to construct eight thermal power units, each with an 800 MW capacity, totaling 6,400 MW. Announced on August 11, 2025, this significant order will be executed by L&T Energy - CarbonLite Solutions (LTECLS), the company's specialized division for advanced power and low-carbon technologies. The scope includes comprehensive design, engineering, manufacturing, supply, and commissioning of Boiler-Turbine-Generator (BTG) packages, along with auxiliaries and associated mechanical, instrumentation, and electrical systems.

Subramanian Sarma, L&T's Deputy Managing Director and President, highlighted the deal's importance, stating, "In today's dynamic energy landscape, where India's demand for reliable and affordable power continues to grow, this order reinforces our role as a leading partner in building critical energy infrastructure." The project strengthens L&T's long-standing partnership with Adani Power, India's largest private-sector thermal power producer with over 18,000 MW of installed capacity.

The announcement triggered positive market sentiment, with L&T's shares rising 1.79% to ₹3,672 and Adani Power's stock gaining 3.48% to ₹597 on August 11, 2025. Posts on X echoed this enthusiasm, describing the deal as a "mega boost" for India's power sector. This contract aligns with India's growing energy needs and Adani Power's plan to expand its capacity by 12,520 MW by March 2030.

L&T's robust order book, valued at ₹5.1trillion as of September 2024, reflects its dominance in infrastructure and energy projects. The company anticipates order prospects worth ₹15 lakh crore by March 2026, with 60% from international markets. This deal not only bolsters L&T's domestic portfolio but also underscores its expertise in delivering large-scale energy projects, positioning it as a key player in India's energy infrastructure development.

Mahindra to Boost EV Exports to UK Under New Trade Pact

Bhopal: Mahindra & Mahindra, a leading Indian automaker, has announced plans to export it made-in-India electric vehicles (EVs) to the United Kingdom, capitalizing on the recently signed India-UK Free Trade Agreement (FTA). The announcement, made on August 13, 2025, aligns with India's push to strengthen its position in the global EV market and leverage favourable trade terms to expand its footprint in Europe.

The FTA, finalized earlier this year, reduces tariffs and simplifies market access, making it an opportune moment for Mahindra to introduce its EV portfolio, including models like the XUV400 and upcoming Born Electric range, to the UK. Mahindra aims to tap into the UK's growing demand for sustainable mobility, where EV sales are projected to rise significantly by 2030. The company's focus on affordability and performance positions it to compete with global brands in the UK's competitive EV market.

Mahindra's EV strategy includes scaling up production at its Chakan facility in Maharashtra, which is being upgraded to meet international standards. The company also plans to collaborate with local UK partners for distribution and after-sales support.

This export push follows Mahindra's strong domestic performance, with its EV division reporting a 30% sales increase in FY25. The company's investment in battery technology and sustainable manufacturing aligns with the UK's net-zero goals, enhancing its appeal to environmentally conscious consumers. Analysts estimate that the FTA could boost India's automotive exports to the UK by 15% annually, with Mahindra poised to capture a significant share.

By entering the UK, Mahindra not only strengthens its global brand but also contributes to India's economic diplomacy. The move is expected to create jobs in both countries and foster technology exchange, positioning Mahindra as a key player in the global EV revolution.

नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पास, जानिए क्या है इसमें खास

भोपाल: लोकसभा में सोमवार को नया इनकम टैक्स बिल 2025 शोर-शराबे के बीच पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल का संशोधित संस्करण पेश किया, जो 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा। यह बिल करदाताओं के लिए कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आइए जानते हैं इस बिल में क्या है खास और यह आम लोगों को कैसे प्रभावित करेगा।

बिल की मुख्य विशेषताएं

1. कर प्रणाली में सरलीकरण:
नए बिल में शब्दों की संख्या को 6 लाख से घटाकर 3 लाख किया गया है, जिससे इसे समझना आसान होगा। यह कदम करदाताओं और कर अधिकारियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

2. नई कर स्लैब संरचना:
बिल में आयकर स्लैब में बदलाव किए गए हैं। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके बाद 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25%, और 24 लाख रुपये से अधिक पर 30% कर लगेगा। यह मध्यम वर्ग के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।

3. देर से रिटर्न दाखिल करने पर रिफंड:
नया बिल उन करदाताओं को राहत देता है जो बीमारी या तकनीकी समस्याओं के कारण समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते। अब ऐसी स्थिति में भी रिफंड का प्रावधान किया गया है।

4. संपत्ति कर में बदलाव:
संपत्ति से होने वाली आय पर कर अब वास्तविक किराए या डीम्ड रेंट (मान्य किराया) में से जो अधिक होगा, उसके आधार पर लगेगा। इससे संपत्ति कर की गणना में पारदर्शिता आएगी।

5. चैरिटेबल ट्रस्ट और एलएलपी के लिए राहत:
बिल में चैरिटेबल ट्रस्टों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटाया गया है। साथ ही, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) हटाने का प्रावधान किया गया है, जिससे इन संस्थाओं को कर प्रक्रिया में आसानी होगी।

6. नया नामकरण:
'एसेसमेंट ईयर' का नाम बदलकर इसे और सरल बनाया जाएगा। यह बदलाव करदाताओं के लिए प्रक्रिया को और स्पष्ट करेगा।
बिल का उद्देश्य और प्रभाव: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल करता है। इसका उद्देश्य आयकर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है। यह बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और पुराने 1961 के कानून को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देगा।
यह बिल मध्यम वर्ग के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया गया है। साथ ही, छोटे व्यवसायों और चैरिटेबल संगठनों को भी राहत मिलेगी।

विशेषज्ञों की राय: कर विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल कर प्रणाली को और पारदर्शी बनाएगा। विशेष रूप से एलएलपी और चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए किए गए प्रावधान छोटे व्यवसायों और सामाजिक संगठनों को बढ़ावा देंगे। साथ ही, देर से रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए रिफंड का प्रावधान तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे करदाताओं के लिए राहत भरा है।

भविष्य की संभावनाएं: नया इनकम टैक्स बिल भारत की कर प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का दावा है कि यह बिल न केवल करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएगा, बल्कि कर संग्रह को भी अधिक प्रभावी बनाएगा। हालांकि,

इस बिल के प्रभाव को समझने के लिए इसे लागू होने के बाद के परिणामों का इंतजार करना होगा।

निष्कर्ष: नया इनकम टैक्स बिल 2025 कर प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह मध्यम वर्ग, छोटे व्यवसायों और चैरिटेबल संगठनों के लिए राहत लेकर आएगा।

स्रोत : लोकसभा टीवी

Hindalco's Strong Q1 Performance Signals Novelis Turnaround

Bhopal: Hindalco Industries has reported a robust 30% surge in consolidated net profit for the June quarter of FY26, reaching ₹4,004 crore, up from ₹3,074 crore in the same period last year. The company's consolidated revenue from operations grew by 13% to ₹64,232 crore, driven by strong performance in its India operations, despite mixed results from its wholly-owned US subsidiary, Novelis. This impressive growth underscores Hindalco's operational resilience and puts the spotlight on Novelis' anticipated revival.
Novelis faced challenges, with its net income dropping 36% to $96 million, primarily due to higher scrap prices and an unfavourable product mix. However, adjusted EBITDA per tonne was $432, down 18% year-on-year, signalling a bottoming out. Hindalco's Managing Director, Satish Pai, expressedoptimism, stating that scrap spreads in the US are improving, turning from a headwind to a tailwind. He anticipates a stronger performance from Novelis in the second half of FY26, driven by cost reduction measures and better scrap price dynamics.
In India, Hindalco's upstream aluminium business saw a 17% rise in EBITDA to ₹4,080 crore, with EBITDA per tonne up 15% to $1,467. The downstream aluminium segment performed exceptionally, with EBITDA per tonne soaring 92% to $264, and overall EBITDA hitting a record ₹229 crore, up 108% year-on-year. The copper business also contributed positively, with EBITDA at ₹673 crore, supported by higher sulphuric acid realisations despite lower treatment and refining charges.Analysts remain bullish on Hindalco, with firms like Nuvama maintaining a 'Buy' rating and a target price of ₹776, citing Novelis' potential recovery by Q4 FY26. The closed marginally lower at ₹666.95 on the BSE, reflecting market caution but strong long-term potential.
Hindalco's Q1 results highlight its ability to navigate global challenges while capitalizing on domestic strengths. With Novelis poised for a rebound and India's aluminium and copper businesses firing on all cylinders, Hindalco is well-positioned for sustained growth. Investors will closely watch the coming quarters for signs of Novelis' full recovery and further margin improvements.

Source: NSE

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	24631	25125	24914	24772	24561	24419	24208	24066
BANK NIFTY	55342	56251	55907	55624	55280	54997	54653	54370
SENSEX	80598	82342	81669	81133	80460	79924	79251	78715
FINNIFTY	26333	26775	26599	26466	26290	26157	25981	25848
MIDCAP	12639	13052	12896	12767	12611	12482	12326	12197
ACC	1781	1818	1810	1796	1788	1774	1766	1752
AXISBANK	1068	1101	1089	1078	1066	1055	1043	1032
ABCAPITAL	272	282	278	275	271	268	264	261
BHARTIARTL	1870	1924	1903	1887	1866	1850	1829	1813
BHEL	222	233	230	226	223	219	216	212
BIOCON	359	410	389	374	353	338	317	302
CDSL	1560	1227	1405	1483	1661	1739	1917	1995
DATAPATTERN	2520	2824	2704	2612	2492	2400	2280	2188
ESCORTS	3401	3554	3487	3444	3377	3334	3267	3224
EICHERMOTOR	5747	5941	5862	5804	5725	5667	5588	5530
FEDERAL BANK	196	201	199	198	196	195	193	192
GRINFRAPOJECT	1252	1345	1309	1280	1244	1215	1179	1150
HDFCBANK	1988	2031	2015	2001	1985	1971	1955	1941
HCLTECH	1489	1565	1540	1515	1490	1465	1440	1415
HINDUNILVR	2475	2581	2559	2517	2495	2453	2431	2389
HAL	4544	4876	4722	4633	4479	4390	4236	4147
HYUNDAI	2230	2468	2369	2299	2200	2130	2031	1961
IOC	140	148	146	143	141	138	136	133
ICICIBANK	1427	1465	1452	1439	1426	1413	1400	1387
INFY	1447	1528	1499	1473	1444	1418	1389	1363
ITC	412	427	423	418	414	409	405	400
KOTAKBNK	1981	2039	2018	1999	1978	1959	1938	1919
LICHOUSING	570	586	581	576	571	566	561	556
LT	3672	3855	3791	3732	3668	3609	3545	3486
LUPIN	1960	2110	2060	2010	1960	1910	1860	1810
MARUTI	12905	13544	13250	13078	12784	12612	12318	12146
M&M	3265	3502	3400	3333	3231	3164	3062	2995
MGL	1315	1410	1389	1352	1331	1294	1273	1236
MAZGAONDOC	2718	2921	2845	2782	2706	2643	2567	2504
PFC	416	444	435	425	416	406	397	387
RECLTD	382	397	393	388	384	379	375	370
RELIANCE	1372	1435	1419	1395	1379	1355	1339	1315
SBIN	826	853	841	833	821	813	801	793
SUNPHARMA	1633	1727	1689	1661	1623	1595	1557	1529
SHRIRAMFINANCE	616	634	628	622	616	610	604	598
TITAN	3485	3676	3605	3545	3474	3414	3343	3283
TCS	3023	3150	3123	3073	3046	2996	2969	2919
TATAMOTORS	664	718	693	678	653	638	613	598
UPL	683	711	704	693	686	675	668	657
VALIENT	373	430	402	387	359	344	316	301
WIPRO	247	259	254	250	245	241	236	232

रेडिको, शाहरुख खान और निखिल कामथ ने मिलकर शुरू की लक्जरी स्पिरिट्स कंपनी

भोपाल: बॉलीवुड आइकन शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन खान और ज़ेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ ने मिलकर एक नई अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी, डी'यावोल स्पिरिट्स, लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। यह घोषणा 12 अगस्त 2025 को की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय लक्जरी स्पिरिट्स को वैश्विक मंच पर ले जाना है। यह साझेदारी भारतीय ब्रांड्स को विश्व स्तर पर स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है।

डी'यावोल स्पिरिट्स प्रीमियम टकीला और स्कॉच सहित उच्च गुणवत्ता वाले पेय लॉन्च करेगी। रेडिको खेतान, 75 साल पुरानी डिस्टिलरी, अपनी विशेषज्ञता और उत्पादन क्षमता के साथ इस उद्यम का आधार बनाएगी। शाहरुख खान, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक भी हैं, अपने वैश्विक प्रभाव और ब्रांड अपील के साथ कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। निखिल कामथ, जिन्होंने ज़ेरोधा के माध्यम से वित्तीय बाजारों में क्रांति लाई, इस उद्यम में नवाचार और रणनीतिक दृष्टिकोण लाएंगे।

रेडिको खेतान के प्रबंध निदेशक ने कहा कि यह साझेदारी लक्जरी स्पिरिट्स के क्षेत्र में गेम-चेंजर साबित होगी। पहला उत्पाद, एक प्रीमियम टकीला, जल्द ही बाजार में आएगा, जिसे वैश्विक उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कदम भारत के तेजी से बढ़ते अल्कोहलिक बेवरेज बाजार, जो 2028 तक $64 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, में रेडिको की स्थिति को और मजबूत करेगा। विश्लेषकों का मानना है कि यह साझेदारी न केवल रेडिको की ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगी, बल्कि भारत को वैश्विक लक्जरी स्पिरिट्स बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगी। यह उद्यम भारतीय नवाचार और वैश्विक अपील का एक शानदार उदाहरण है, जो भविष्य में और अधिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।

स्रोत : दा हिन्दू बिज़नेस लाइन

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in